भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1621

13/02/2026 को उत्तरार्थ

विषयः उत्तराखंड में एसएमएएम योजना का कार्यान्वयन

1621. श्री महेंद्र भट्टः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कुल कितने कृषकों द्वारा आवेदन किए गए हैं;

(ख) राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 90% अंश के रूप में अभी तक कुल कितनी निधि जारी कर दी गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): वर्ष 2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तथा फार्म पावर की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण की पहुँच बढ़ाना है तथा छोटी भू-धारिता और कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल इकॉनोमी ऑफ स्केल की क्षतिपूर्ति लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देना है। इस योजना का कर्यान्वयन उत्तराखंड राज्य में भी केंद्र और राज्य के बीच 90:10 की फंड शेयरिंग पद्धति के आधार पर किया गया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान (दिनांक 09.02.2026 तक), उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार की ओर से 220.65 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। कृषि विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान (दिनांक 09.02.2026 तक), पोर्टल पर प्राप्त कुल 45165 आवेदनों में से एसएमएएम योजना के तहत 27562 किसानों को वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

*****